कार्यालय मुख्यआयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र),जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

SPEAKING ORDER/स्पीकिंग आदेश

Establishment Order No:- CCU-05/2026

(स्थापना आदेश संख्या:- सीसीयू-05/2026)

Dated:-As per E-signature

दिनांक :-ई-हस्ताक्षर के अनुसार

(Arising out of O.A. No. 426/2020 filed by Angad Meena & Ors. Vs Union of India & Ors.)

(अंगद मीना एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 426/2020 से उत्पन्न)

BRIEF FACTS OF THE CASE/मामले के संक्षिप्त तथ्य:-

Shri Angad Meena & 2 other applicants, had filed the O.A. No. 426/2020 before the Hon'ble CAT, Jaipur Bench, Jaipur seeking following reliefs :

श्री अंगद मीना एवं 2 अन्य आवेदकों ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), जयपुर खंडपीठ, जयपुर के समक्ष मूल आवेदन (OA) संख्या 426/2020 दायर की, जिसमें उनके द्वारा निम्न विवरणानुसार राहतें मांगी गई हैं।

"A) issue appropriate order or direction, directing the respondents to pass necessary orders to fix the applicants at Grade Pay of Rs. 5400 /- in PB-2 and extend the benefit of fixation at Grade Pay of Rs. 5400/- in PB-2 upon completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4800 in PB-2, along with all consequential and incidental benefits thereto along with grant of arrears at an earliest;

B) Costs and Incidentals;

C) Pass such further or other order or orders and other relief/s as may be deemed fit and proper in the peculiar facts & circumstances of the present case."

2. In the aforesaid O.A., there were 3 applicant's namely (i) Shri Angad Meena; (ii) Shri Mahesh Kumar & (iii) Shri Manoj Kumar Meena. Since, Shri Angad Meena had been repatriated to his parent Zone on 18.06.2024 the Hon'ble Tribunal was informed accordingly that now Jaipur Zone is not competent to consider his prayer. The Hon'ble CAT vide order dated 30th October 2025 has disposed of the O.A. No. 426/2020 titled Angad Meena & Ors. Vs. UOI & Ors., with the following directions:-

उपरोक्त मूल आवेदन (O.A.) में तीन आवेदक थे, नामित (i) श्री अंगद मीना (ii) श्री महेश कुमार एवं (iii) श्री मनोज कुमार मीना, चूँकि श्री अंगद मीना को दिनांक 18.06.2024 को उनके मूल ज़ोन में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था, अतः माननीय अधिकरण को इस संबंध में अवगत कराया गया कि अब जयपुर परिक्षेत्र उनकी प्रार्थना पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं है। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने अपने आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2025 द्वारा मूल आवेदन संख्या 426/2020, शीर्षक अंगद मीना एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया है-

> *"At the very outset, learned counsel for the applicants states that the applicants have filed the representation dated 04.01.2020 qua applicant no. 2 and representation dated 08.01.2020 (Annexure A/13) qua applicant no. 3 which are still pending with the respondents.*
>
> *The applicants are satisfied if a direction be given to the respondents to decide the pending representations within a timeframe.*
>
> *Respondents• are directed to decide the pending representation dated 04.01.2020 qua applicant no. 2 (Annexure A/13) and representation dated 08.01.2020 (Annexure A/13) qua applicant no. 3 and pass a reasoned and speaking order within four weeks from the date of receipt of a certified copy of this order.*
>
> *Accordingly, the present Original Application is disposed of. No costs."*

3. The certified copy of the Order dated 30th October 2025 had been issued on 7th November 2025.

दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के आदेश की प्रमाणित प्रति 7 नवम्बर 2025 को जारी की गई थी।

4. Prior to filing O.A. under examination, Shri Mahesh Kumar & Shri Manoj Kumar Meena, both superintendents had submitted representations seeking the reliefs claimed as above. The applicants were informed that the issue had been forwarded to the Board and their cases will be considered in accordance with the instructions/directions received from the Board. The issue was under consideration meanwhile they approached the Hon'ble Tribunal.

उपरोक्त मूल आवेदन (OA) दायर किये जाने से पूर्व, श्री महेश कुमार एवं श्री मनोज कुमार मीना, दोनों अधीक्षक, ने उपरोक्त राहतों की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे। आवेदकों को सूचित किया गया कि यह विषय बोर्ड को अग्रेषित कर दिया गया है तथा उनके मामलों पर बोर्ड से प्राप्त होने वाले निर्देशों/आदेशों के अनुसार विचार किया जायेगा। जब उक्त विषय विचाराधीन था, इस दौरान उन्होंने माननीय अधिकरण का रुख किया।

5. Since, the issue involved in the matter is related to the policy formulated by the DoPT & the Board, the matter was taken up with the Board vide this office letter even F.No. dated 03.12.2025. The Board after examination, vide letter F. No. A 23011/44/2020 Ad IIA-(Pt.2) dated 10th December 2025, has directed to implement the Order dated 30th October 2025 of the Tribunal, in respect of the individual applicants (i.e. applicant no. 2 Sh. Mahesh Kumar and applicant no. 3 Sh. Manoj Kumar Meena) on in personam basis only, by way of issuing the speaking order provided that these cases are similar to the case covered in the Hon'ble Madras High court dated 06.09.2010 in W.P. No. 13225/2010 passed in M. Subramaniam case against which SLP was dismissed.

चूँकि मामले में निहित विषय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और बोर्ड द्वारा निर्मित नीति से संबंधित है, अतः प्रकरण को इस कार्यालय के पत्र फाईल सम संख्या दिनांक 03.12.2025 के द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने जांच के पश्चात, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 के पत्रांक F.No. A-23011/44/2020Ad IIA-(Pt.2) के माध्यम से निर्देश दिया कि अधिकरण के दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के आदेश को, केवल आवेदक संख्या 2 अर्थात् श्री महेश कुमार एवं आवेदक संख्या 3 अर्थात् श्री मनोज कुमार मीना के संदर्भ में, इन पर्सोनम आधार पर एक सकारण आदेश जारी करते हुए लागू किया जाये, बशर्ते कि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के 06 सितम्बर 2010 के आदेश जो कि डब्ल्यू.पी.

सं. 13225/2010- एम. सुब्रमण्यम मामले में पारित हुआ है एवं जिसके विरुद्ध दायर SLP को खारिज किया गया था,से तथ्यात्मक रूप से समान हो।

DISCUSSION AND FINDINGS/चर्चा एवं निष्कर्ष:-

6. In pursuance to Hon'ble CAT Jaipur Bench aforesaid Order dated 30th October 2025, the matter has been examined thoroughly and it is observed that Shri Angad Meena & Others had filed the Original Application No. 426/2020 before the Hon'ble Tribunal to issue appropriate order or direction, directing the respondents to pass necessary orders to fix the applicants at Grade Pay of Rs. 5400 /- in PB-2 and extend the benefit of fixation at Grade Pay of Rs. 5400/- in PB-2 upon completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4800 in PB-2, along with all consequential and incidental benefits thereto along with grant of arrears at an earliest;

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, मामले की संपूर्ण जांच की गई। यह पाया गया कि श्री अंगद मीना एवं अन्य ने माननीय अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन संख्या 426/2020 प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रतिवादियों को उपयुक्त आदेश अथवा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था, ताकि आवेदकों का वेतनमान पीबी-2 में ग्रेड पे ₹5400/- पर निर्धारित किया जाये तथा पीबी-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में चार वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर पीबी-2 में ग्रेड पे ₹5400/- पर वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किया जाये, साथ ही उससे संबंधित सभी अनुषंगी एवं आनुषंगिक लाभ प्रदान किये जाये तथा समस्त बकाया राशि (एरियर) का भुगतान यथाशीघ्र किया जाये।

7. The instructions regarding grant of Non-Functional Grade issued by the DoP&T and CBIC from time to time as well as various orders passed by the Hon'ble CAT/Courts are, briefed as under:

गैर-कार्यात्मक ग्रेड प्रदान करने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों तथा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

7.1. The 6th Central Pay Commission gave various recommendations for fixing of pay of employees of the Government of India. The recommendations accepted by the Government were notified vide GSR

622 (E) dated 29th August 2008 as Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008. As per Section II of Part-C of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, it was informed that the revised pay structure mentioned in Column (5) and (6) of this part of the Notification for the posts mentioned in Column (2) have been approved by the Government. In Section – II of the said Notification, it is laid down against Sl. No. 9, under the Head 'Department of Revenue, Ministry of Finance' that Income Tax Officers/Superintendents/Appraisers etc. (Customs & Central Excise) be placed in the Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised) in Pay Band–2 with Grade Pay of Rs. 4800/-. Further it has been mentioned that they will be placed in Revised Pay Scale of Rs. 8,000–13,500 in PB-2 with Grade Pay of Rs. 5,400/- after 4 years. Section I of Part A of the First Schedule to the Rules, provides the Revised Pay Bands and Grade Pays for posts carrying scales in Group 'A,' 'B,' 'C' & 'D' except posts for which different revised scales are notified separately. As per the same, the revised pay structure for employees in the Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised) has been rectified as Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4800/-.

छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए विभिन्न सिफारिशें दीं। सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों को दिनांक 29 अगस्त 2008 को GSR 622(E) के माध्यम से केंद्रीय सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2008, में अधिसूचित किया गया। केंद्रीय सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियमों के पार्ट- सी के भाग II के अनुसार सूचित किया गया कि अधिसूचना के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों के लिए कॉलम (5) और (6) में उल्लिखित संशोधित वेतन संरचना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त अधिसूचना के भाग II में, क्र. सं. 9 के अंतर्गत, 'वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग' के शीर्षक के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि आयकर अधिकारी/अधीक्षक/मूल्यांकक आदि (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) को वेतनमान ₹7500–12000 (पूर्व-संशोधित) में पे बैंड–2, ग्रेड पे ₹4800/- के साथ रखा जाये। इसके अतिरिक्त उल्लेख किया गया है कि 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद उन्हें ₹8000–13500 में संशोधित वेतनमान, पे बैंड–2 के साथ ग्रेड पे ₹5400/- में रखा जायेगा। नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग A के सेक्शन I में, समूह 'A', 'B', 'C' और 'D' में वेतनमान वाले पदों के लिए संशोधित वेतनबैंड और ग्रेड पे प्रदान किये गये हैं, सिवाय उन पदों के जिनके लिए अलग से संशोधित वेतनमान अधिसूचित किया गया है। इसके अनुसार, पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500–12000 वाले कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना ₹9300–34800 के वेतनबैंड में, ग्रेड पे ₹4800/- के साथ निर्धारित की गई है।

7.2. The Ministry, vide letter under F. No. A. 26017/98/2008-Ad.IIA dated 21st November 2008, referred to Part – C, Section – II of the CCS

(Revised Pay) Rules, 2008, wherein under the heading of 'Ministry of Finance, Department of Revenue' at Sl. No. 9, it is indicated that Superintendents, Appraisers, etc. (Customs and Central Excise) [who are in the pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000] shall be granted Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-2 [corresponding to pre-revised scale of Rs. 8,000-13,500], after 4 years of service. Further, in Clause (x)(e) of Para 1 of the RESOLUTION of the Department of Expenditure dated 29th August 2008 also it was indicated that "*Group-B Officers of Departments of Posts, Revenue etc. will be granted Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-2 on non-functional basis after 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4800/- in PB-2.*" The Ministry in Para 3 of aforesaid letter dated 21st November 2008, stated that the Department of Expenditure has clarified that the 4-years period is to be counted with effect from the date on which an officer is placed in the Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised).

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 नवंबर 2008 को पत्रांक F. No. A. 26017/98/2008-Ad.IIA मे केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008, भाग C, सेक्शन II का संदर्भ दिया, जिसमें 'वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग' के शीर्षक के अंतर्गत क्र. सं. 9 में यह दर्शाया गया है कि अधीक्षक, मूल्यांकक आदि (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क) [जो पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500–12000 में हैं] को 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- प्रदान किया जाएगा [जो पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹8000–13500 के अनुरूप है]। इसके अतिरिक्त, व्यय विभाग संकल्प (Department of Expenditure Resolution) दिनांक 29 अगस्त 2008 के पैरा 1 की उपधारा (x)(e) में भी यह संकेत दिया गया है कि डाक, राजस्व आदि विभागों के समूह-बी अधिकारी नियमित रूप से ग्रेड पे ₹4800/- में PB-2 में 4 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरांत गैर-कार्यात्मक आधार पर PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- प्राप्त करेंगे। मंत्रालय ने अपने पत्रांक दिनांक 21 नवंबर 2008 के अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया कि व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने स्पष्ट किया है कि 4-वर्ष की अवधि की गणना उस तिथि से की जायेगी जिस दिन किसी अधिकारी को ₹7500-12000 (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में रखा गया हो।

7.3. Further, the Ministry vide Para 3 of letter F. No. A.26017/98/2008-Ad.IIA dated 11th February 2009, on the issue clarified that the matter has been examined in consultation with the Department of Expenditure who have clarified the matter as under:-

इसके अलावा, मंत्रालय ने दिनांक 11 फरवरी 2009 के पत्रांक F. No. A.26017/98/2008-Ad.IIA के अनुच्छेद 3 में इस विषय पर स्पष्ट किया कि

मामले की जांच व्यय विभाग (Department of Expenditure) के परामर्श से की गई, जिन्होंने इस विषय पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:-

"…. Non-functional upgradation to the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Pay Band PB-2 can be given on completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2 (pre-revised scale of Rs. 7500-12000) after regular promotion and not on account of financial upgradation due to the ACP."

7.4. The Hon'ble CAT, Madras Bench, vide its order dated 19th April 2010 had dismissed the O.A. No. 167/2009 seeking grant of Grade Pay of Rs. 5,400/- and the consequential benefits with effect from 01st January 2008 as per the orders of the Government of India accepting the recommendations of the 6th CPC. Being aggrieved by the dismissal of the aforesaid O.A., Shri M. Subramaniam filed W.P. No. 13225 of 2010 before the Hon'ble High Court of Judicature at Madras. The Hon'ble High Court of Judicature at Madras, vide order dated 06th September 2010, made the following observations:-

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ ने दिनांक 19 अप्रैल 2010 के अपने आदेश के माध्यम से मूल आवेदन संख्या 167/2009, जिसमें ग्रेड पे ₹5400/- और इसके अनुषंगिक लाभ 01 जनवरी 2008 से प्राप्त करने की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया था, जो कि भारत सरकार द्वारा छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6th CPC) की सिफारिशों को स्वीकार करने के आदेशों के अनुसार था। उक्त मूल आवेदन के खारिज किये जाने से असंतुष्ट होकर, श्री एम. सुब्रमण्यम ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 13225/2010 दायर की। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 06 सितंबर 2010 के अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:-

> *"7. We are unable to agree with this clarification given by the Under Secretary to the Government of India, since in an earlier clarification dated 21.11.2004 (correct date 21.11.2008) of the Deputy Secretary to Government of India, it was clarified as to how the 4-year period is to be counted for the purpose of granting non-functional upgradation to Group-B Officer, i.e. whether the 4-year period is to be counted with effect from the date on which the officer is placed in the pay scale of Rs. 7,500-12000 (pre-revised) or with effect from 01.01.2006, i.e. the date on which the recommendation of the 6th CPC came into force. It was clarified that the 4-year period is to be counted with effect*

from the date on which an officer is placed in the pay scale of Rs. 7,500-12000 (pre-revised).

8. Thus, if an officer has completed 4 years on 01.01.2006 or earlier, he will be given the non-functional upgradation with effect from 01.01.2006 and if the officer completes 4-years on a date after 01.01.2006, he will be given non-functional upgradation from such date on which he completes 4-year in the pay scale of Rs. 7,500-12,000/- (pre-revised), since the petitioner admittedly completed 4-year period in the pay scale of Rs. 7500-12000 as on 01.01.2008, he is entitled to the grade pay of Rs. 5400/-. In fact, the Government of India having accepted the recommendations of the 6th Pay Commission, issued a resolution dated 29.08.2008 granting grade pay of Rs. 5400/- to Group B officers in Pay Band-2 on non-functional basis after four years of regular service in the grade pay of Rs. 4800/- in Pay Band-2. Therefore, denial of the same benefit to the petitioner based on the clarification issued by the Under Secretary to the Government of India was contrary to the above said clarification and without amending the rules of the revised pay scale, such decision cannot be taken. Therefore, we are inclined to interfere with the order of the Tribunal.

9. *Accordingly, the Writ Petition is allowed setting aside the order of the Tribunal, dated 19.4.2010 passed in O.A. No. 167 of 2009. The respondents are directed to extend the benefit of grade pay of Rs. 5,400/- to the petitioner from 01.01.2008 as per the resolution dated 29.08.2010 (correct date 29.08.2008)."*

7.5. Department of Expenditure, vide Resolution No. 1/1/2008-IC dated 29th August 2008, has specified that the Group 'B' officers of the Department of Revenue will be granted Grade Pay of Rs. 5,400/- in Pay Band–2 on non-functional basis after 4 (four) years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in Pay Band– 2. Para 1(x)(e) of the resolution dated 29th August 2008 issued by the Department of Expenditure is reproduced below for the sake of convenience :-

व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने दिनांक 29 अगस्त 2008 के संकल्प संख्या 1/1/2008-IC के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग के समूह 'B' के अधिकारियों को PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में चार वर्ष नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात PB-2 में गैर-कार्यात्मक आधार पर ग्रेड पे

₹5400/- प्रदान किया जायेगा। सुविधा के लिए व्यय विभाग द्वारा 29 अगस्त 2008 के संकल्प का अनुच्छेद 1(x)(e) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

"Group 'B' officers of Department of Posts, Revenue etc. will be granted grade pay of Rs. 5400/- in PB-2 on non-functional basis after 4 years of regular service in the grade of Rs. 4800/- in PB-2."

7.6. Further, on receipt of some other references from field formations of CBEC (now CBIC) as to whether the officers who have got the pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000 by virtue of financial upgradation under ACP will also be entitled to the benefit of further non-functional upgradation on completion of 4 years in the prescribed Pay Scale of Rs. 7,500-12,000 (pre-revised) in terms of the recommendations of the 6th CPC as accepted by the Government, the matter was again examined at length in consultation with the Department of Expenditure and it was clarified as under :-

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (अब केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के क्षेत्रीय गठन से यह संदर्भ प्राप्त होने पर कि क्या वे अधिकारी जिन्होंने ACP के तहत वित्तीय उन्नयन के कारण पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500-12000 प्राप्त किया है, उन्हें भी निर्धारित वेतनमान ₹7500-12000 (पूर्व-संशोधित) में 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा स्वीकार की गई छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6th CPC) की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त गैर-कार्यात्मक उन्नयन का लाभ मिलेगा या नहीं, इस विषय को पुनः व्यय विभाग (Department of Expenditure) के परामर्श से विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया और निम्नानुसार स्पष्ट किया गया:-

".......Non-functional upgradation to the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Pay Band PB-2 can be given on completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2 (pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000) after regular promotion and not on account of financial upgradation due to ACP."

Accordingly, a clarification to this effect was issued vide Board's letter F. No. A.26017/98/2008-Ad.II.A dated 11th February 2009.

इसके अनुरूप, इस संदर्भ में स्पष्टीकरण बोर्ड के पत्रांक F. No. A.26017/98/2008-Ad.II.A दिनांक 11 फरवरी 2009 के माध्यम से जारी किया गया।

7.7. In view of the above facts, the order of the Hon'ble High Court of Judicature at Madras was examined in light of clarification dated 11th February 2009 on grant of Non-functional grade in the Grade Pay of Rs. 5,400/- in PB-2 to Group 'B' officers in consultation with Department of Expenditure in the case of Shri M. Subramaniam Vs. Union of India.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश की जांच की गई और श्री एम. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ मामले में व्यय विभाग (Department of Expenditure) के परामर्श से समूह 'B' अधिकारियों को PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- में गैर-कार्यात्मक ग्रेड प्रदान करने के संबंध में दिनांक 11 फरवरी 2009 के स्पष्टीकरण के आधार पर समीक्षा की गई।

7.8. Department of Expenditure, vide UO No. 15(23)E.III(B)/2010 dated 24th December 2010, clarified that non-functional upgradation to the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Pay Band PB-2 can be given on completion of 4 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/- in PB-2 (pre-revised scale of Rs. 7,500-12,000) after regular promotion and not on account of financial upgradation due to ACP. In the case of Shri M. Subramaniam, he was holding the post of Inspector and was granted the Grade Pay of Rs. 4,800/in PB-2 under ACP Scheme. He was not promoted to the post of Superintendent/Appraiser and as such, he had not rendered any regular service in the Grade Pay of Rs. 4,800/-. Therefore, he could not be extended the benefit of the Grade Pay of Rs. 5,400/- after 4 years of service in the Grade Pay of Rs. 4,800/-. DoP&T also endorsed the view of the Department of Expenditure.

व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने UO संख्या 15(23)E.III(B)/2010 दिनांक 24 दिसंबर 2010 के माध्यम से स्पष्ट किया कि PB-2 वेतन बैंड में ग्रेड पे ₹5400/- में गैर-कार्यात्मक उन्नयन केवल तब दिया जा सकता है जब अधिकारी ने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- (पूर्व-संशोधित वेतनमान ₹7500–12000) में नियमित सेवा के 4 वर्ष पूर्ण कर लिये हों, और यह नियमित पदोन्नति के आधार पर होना चाहिए, सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के आधार पर नहीं। श्री एम. सुब्रमण्यम के मामले में, वह निरीक्षक के पद पर तैनात थे

और उन्हें सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के तहत PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- प्रदान किया गया था। उन्हें अधीक्षक/मूल्यांकक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था और इसलिए उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में कोई नियमित सेवा नहीं दी थी। अतः उन्हें PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में 4 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बाद ग्रेड पे ₹5400/- का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भी व्यय विभाग के इस दृष्टिकोण को अनुमोदित किया।

7.9. Accordingly, an SLP No. 15627 of 2011 was filed before the Hon'ble Supreme Court (subsequently converted to Civil Appeal No. 8883/2011) against the Hon'ble Madras High Court's Order dated 06th September 2010 in W.P. No. 13225/2010. The Hon'ble Supreme Court, vide order dated 10th October 2017, did not see any ground to interfere with the impugned order and, accordingly, dismissed the appeal and the SLP filed by the Union of India.

अतः, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06 सितंबर 2010 के आदेश (रिट याचिका सं. 13225/2010) के खिलाफ, भारत संघ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP संख्या 15627/2011 दायर की गई (जिसे बाद में सिविल अपील संख्या 8883/2011 में परिवर्तित किया गया)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10 अक्टूबर 2017 के अपने आदेश में विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और तदनुसार अपील और भारत संघ द्वारा दायर SLP को खारिज कर दिया।

7.10. Thereafter, a Review Petition (Civil) No. 2512 of 2018 in Civil Appeal No. 8883 of 2011 was also filed by the Union of India before the Hon'ble Supreme Court, which was also dismissed vide order dated 23rd August 2018, on the ground of delay as well as on merits.

इसके पश्चात, भारत संघ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 8883/2011 में समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 2512/2018 भी दायर की, जिसे 23 अगस्त 2018 के आदेश के माध्यम से, विलंब और याचिका की सामग्री (merits) दोनों आधारों पर खारिज कर दिया गया।

8. Since, the issue involved in the matter is related to the policy, Board's directions regarding implementation of the aforesaid Order dated 30th October 2025 of the Tribunal were sought vide letter dated 03rd December 2025. The Board after examination, vide letter F. No. A 23011/44/2020 Ad IIA-(Pt.2) dated 10th December 2025, has directed to implement the Order

dated 30th October 2025 of the Tribunal, in respect of the individual applicants (i.e. applicant no. 2 Sh. Mahesh Kumar and applicant no. 3 Sh. Manoj Kumar Meena) on in personam basis only, by way of issuing the speaking order provided that these cases are similar to the case covered in the Hon'ble Madras High court dated 06.09.2010 in W.P. No. 13225/2010 passed in M. Subramaniam case against which SLP was dismissed.

चूँकि, इस मामले में निहित विषय, नीति से संबंधित है, अतः अधिकरण के दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में बोर्ड के निर्देश दिनांक 03 दिसम्बर 2025 के पत्र के माध्यम से मांगे गये। बोर्ड ने जांच के पश्चात, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 के पत्रांक F.No. A-23011/44/2020 Ad IIA-(Pt.2) के माध्यम से निर्देश दिया कि अधिकरण के दिनांक 30 अक्टूबर 2025 के आदेश को, केवल आवेदक संख्या 2 अर्थात् श्री महेश कुमार एवं आवेदक संख्या 3 अर्थात् श्री मनोज कुमार मीना के संदर्भ में, इन पर्सोनम आधार पर एक सकारण आदेश जारी करते हुए लागू किया जाये, बशर्ते कि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के 06 सितम्बर 2010 के आदेश जो कि डब्ल्यू.पी. सं. 13225/2010- एम. सुब्रमण्यम मामले में पारित हुआ है एवं जिसके विरुद्ध दायर SLP को खारिज किया गया था,से तथ्यात्मक रूप से समान हो।

9. While examining the case, it is observed, on the basis of facts mentioned in the aforesaid Order dated 06th September 2010 of the Hon'ble Madras High Court, that Shri M. Subramaniam joined service as Inspector of Central Excise on 16th January 1992. The benefit of first financial up-gradation was granted to the applicant with effect from 1st January 2004 in the pay scale of Rs. 7500-250-12000 (revised as grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 in 6th CPC and further revised as Level-8 Rs. 47600- 151100 in 7th CPC) vide order dated 11th August 2004 on the basis of the ACP Scheme. He was drawing the pay scale of Rs. 7500-250-12000 being the pay scale of Superintendent of Central Excise. Shri M Subramaniam filed O.A. No. 167/2009 in the Hon'ble CAT, Madras Bench. The Tribunal rejected the same vide Order dated 19th April 2010.

मामले की जांच करते समय, यह देखा गया कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06 सितंबर 2010 के आदेश में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर, श्री एम. सुब्रमण्यम ने 16 जनवरी 1992 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में निरीक्षक के रूप में सेवा में प्रवेश किया। पहले वित्तीय उन्नयन का लाभ याचिकाकर्ता को ACP योजना के आधार पर दिनांक 11 अगस्त 2004 के आदेश के माध्यम से 1 जनवरी 2004 से वेतनमान रु.7500-250-12000 (छठे केंद्रीय वेतन आयोग में PB-2 में ग्रेड पे रु.4800/- के रूप में संशोधित और सातवें

केंद्रीय वेतन आयोग में स्तर-8 रु.47600-151100 में पुनः संशोधित) में प्रदान किया गया। वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक के वेतनमान रु.7500-250-12000 में वेतन प्राप्त कर रहे थे। श्री एम. सुब्रमण्यम ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ में मूल आवेदन संख्या 167/2009 दायर की, जिसे अधिकरण ने दिनांक 19 अप्रैल 2010 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

9.1 Against the Order of the Tribunal, Shri Subramaniam filed Writ Petition No. 13225/2010 before the Hon'ble High Court of Madras. The Hon'ble Court vide Order dated 06th September 2010 allowed the Writ Petition filed by the applicant and set aside the order of the Hon'ble CAT, Madras Bench dated 19th April 2010 passed in the O.A. No. 167/2009. The Hon'ble High Court ordered to extend the benefit of Grade Pay of Rs 5400/- to the petitioner from 1st January 2008 as per the Resolution dated 29th August 2010 (correct date 29th August 2008). Further, the Civil Appeal No 8883/2011 and Review Petition filed by UOI against the said order was also dismissed by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated 10th October 2017.

अधिकरण के आदेश के विरुद्ध, श्री सुब्रमण्यम ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13225/2010 दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 06 सितंबर 2010 के अपने आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और मूल आवेदन संख्या 167/2009 में दिनांक 19 अप्रैल 2010 के माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 29 अगस्त 2008 के संकल्प के अनुसार 1 जनवरी 2008 से ग्रेड पे ₹5400/- का लाभ दिया जाये। इसके अतिरिक्त, भारत संघ द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ दायर सिविल अपील संख्या 8883/2011 और समीक्षा याचिका को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10 अक्टूबर 2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

10. The facts of the case in respect of Shri Mahesh Kumar & Shri Manoj Kumar Meena have been examined. On the basis of the records of this office, the service particulars in respect of them are as under:-

श्री महेश कुमार एवं श्री मनोज कुमार मीना के संबंध में मामले के तथ्य जांचे गये हैं। इस कार्यालय के अभिलेखों के आधार पर, उनके सेवा विवरण निम्नानुसार हैं:-

S. No.	Name of the Officer & Date of Birth (Shri)	Designation	Date of promotion to the grade of Superintendent, Group 'B' in grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 (revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100)	Date of grant of grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 (revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100) by way of MACP Scheme	Due date of grant of Non-Functional Upgradation to the grade pay of Rs. 5400 in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800) counting 4 years from the date of grant of GP of Rs. 4800 in PB-2 by the virtue of MACP Scheme
1	2	3	4	5	6
01.	Mahesh Kumar (25.01.1979)	Superinte-ndent	28.09.2022	16.09.2015	16.09.2019
02.	Manoj Kumar Meena (27.09.1982)	Superinte-ndent	28.09.2022	09.12.2015	09.12.2019

On examination, it is found that the Applicants No. 2 & 3 of the aforesaid O.A. had been granted 1st financial upgradation under MACPS to the Level-8 in the pay matrix Rs. 47600- 151100 (pre-revised grade pay of Rs. 4800/-in PB-2 in 6th CPC) w.e.f. 16.09.2015 & 09.12.2025 respectively. Now, they are seeking the benefit of non-functional grade pay of Rs 5400/- in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800) on completion of 4 years' service in the grade pay of Rs. 4800/- in terms of judgement dated 06th September 2010 of the Hon'ble High Court of Madras in WP No. 13225/2010 in the case of M. Subramaniam.

जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त वर्णित मूल आवेदन में याचिकाकर्ता संख्या 2 एवं 3 को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) योजना के तहत पहले वित्तीय उन्नयन वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 रु.47600–151100 में (छठे केंद्रीय वेतन आयोग में PB-2 में ग्रेड पे रु.4800/- के रूप में) क्रमशः दिनांक 16.09.2015 एवं 09.12.2025 से प्रदान किया गया। अब, वे PB-2 में ग्रेड पे रु. 5,400/- (सातवीं केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 रु.53100–167800) का लाभ चाहते हैं, जब उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे रु.4800/- में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, जैसा कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 06 सितंबर 2010 के रिट याचिका संख्या 13225/2010, एम. सुब्रमण्यम मामले में अपने निर्णय में निर्देशित किया है।

As per the Hon'ble Court's Order dated 6th September 2010 (supra), Shri M. Subramaniam was granted the pay scale of Rs. 7500-12000 (revised as Grade Pay of Rs. 4800/- in PB-2 in 6th CPC) under ACP Scheme on 1st January 2004 and sought benefits of grade pay of Rs 5400/- w.e.f. 1st January 2008 i.e. on completion of 4 years service in the grade pay of Rs 4800/-in PB-2 granted by virtue of ACP Scheme. The "Modified Assured

Career Progression Scheme" (MACPs) for the Central Government Civilian Employees has been issued in supersession of previous “Assured Career Progression Scheme” (ACP). Thus, the issue of Shri M. Subramaniam and aforesaid officers of Jaipur Zone is identical to each other.

माननीय न्यायालय के दिनांक 06 सितंबर 2010 (सुप्रा) के आदेश के अनुसार, श्री एम. सुब्रमण्यम को सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) योजना के तहत 1 जनवरी 2004 से वेतनमान 7500-12000 प्रदान किया गया और उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 1 जनवरी 2008 से ग्रेड पे ₹5400/- का लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया। केंद्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए ‘संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना’ (Modified Assured Career Progression Scheme – MACPS) को पूर्ववर्ती ‘सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना’ (ACP) के स्थान पर जारी किया गया है। अतः, श्री एम. सुब्रमण्यम और जयपुर परिक्षेत्र के उक्त वर्णित अधिकारियों का मामला परस्पर समान है।

11. In view of above, applying the ratio of the Order dated 06th September 2010 of the Hon'ble Madras High Court in WP No. 13225/2010 in M. Subramaniam case, it is observed that both of the officers as named in the table in para 10 above, who are also the applicant of O.A. No. 426/2020, are entitled to Non Functional Upgradation to the grade pay of Rs. 5400/- in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800 in 7th CPC) on completion of 4 years service in the grade pay of Rs. 4800/- in PB-2 in 6th CPC (revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100 in 7th CPC).

उपरोक्त के दृष्टिगत, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06 सितंबर 2010 के आदेश (रिट याचिका सं. 13225/2010, एम. सुब्रमण्यम मामले) के तात्त्विक अनुप्रयोग के आधार पर, यह पाया गया कि उपरोक्त पैरा 10 में वर्णित तालिका में नामित दोनों अधिकारी, जो कि O.A. No. 426/2020 में आवेदक भी है, PB-2 में ग्रेड पे ₹5400/- (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-9 ₹53100-167800 में संशोधित) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन के हकदार हैं, जब उन्होंने PB-2 में ग्रेड पे ₹4800/- (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 ₹47,600-1,51,100 में संशोधित) में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

12. Accordingly, Shri Mahesh Kumar & Shri Manoj Kumar Meena, both Superintendents, are granted Non Functional Upgradation to the Grade Pay of Rs. 5400/- in PB-2 (revised as Level-9 in pay matrix Rs. 53100-167800 in 7th CPC) on completion of 4 years of continuous service in the Grade Pay of

Rs. 4800/- in PB-2 (revised as Level-8 in pay matrix Rs. 47600-151100 in 7th CPC), from the dates shown against their names in Column No. 6 of the table in para 10 above. The representations of both officers are disposed of accordingly.

अतः, श्री महेश कुमार व श्री मनोज कुमार मीना, दोनों अधीक्षक, को PB-2 में ग्रेड पे ₹4,800/-(सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 ₹47,600–1,51,100 में संशोधित) में 4 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करने पर, पैरा 10 में वर्णित उपरोक्त तालिका में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 6 में दर्शायी गई तिथि से, PB-2 में ग्रेड पे ₹5,400/-(सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 ₹53,100–1,67,800) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जाता है। दोनों अधिकारियों के अभ्यावेदन इस निर्णय के अनुसार निपटाये जाते हैं।

This issues with the approval of the Competent Authority.
यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी किया जाता है।

Digitally signed by
NISHTHA SHARMA
Date: 19-01-2026
15:49:05

(Nishtha Sharma/निष्ठा शर्मा)

Joint Commissioner/संयुक्त आयुक्त

F No.:- GCCO/II/26/1/2020-ADMN Date:-As per E-sign
फा.सं.- GCCO/II/26/1/2020-ADMN दिनांकः-ई-हस्ताक्षर के अनुसार

Copy for information and necessary action to:-
सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषितः-

1. Officers Concerned./ संबंधित अधिकारी |
2. The Pr. Commissioner/Commissioner, CGST Udaipur/Jodhpur.
   प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. उदयपुर/जोधपुर |
3. The Under Secretary (Ad II A). Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi with reference to letter F No A-23011/44/2020-Ad IIA (Pt.2) dated 10.12 2025 for information.
   उप सचिव (Ad II A), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली, को पत्र फा.सं. A-23011/44/2020-Ad IIA (Pt.2) दिनांक 10.12.2025 के संदर्भ में, सूचनार्थ |
4. The PAO, CGST & Customs, Jaipur./वेतन एवं लेखाधिकारी, जयपुर |

5. The CAO /AO (DDO), CGST Udaipur/Jodhpur.
   मुख्य लेखाधिकारी/ प्र.अधिकारी (डी.डी.ओ.) सी.जी.एस.टी. उदयपुर/जोधपुर ।
6. Service Book / Guard file / Notice Board.
   सेवा पुस्तिका/गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड ।
7. Webmaster for uploading a copy of the order on Zonal Website.
   क्षेत्रीय वेबसाइट पर आदेश की प्रति अपलोड करने के लिए वेबमास्टर से अनुरोध है।